(घ) इस सम्बन्ध में वर्ष 1994-95 के लिए सरकार द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) तथा (ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद एक संवर्धनात्मक निकाय है । इस लिए यह सीधे निर्यात नहीं करती है । तथापि, यह जापान सहित विभिन्न देशों में हस्तशिल्प के निर्यातों को बढ़ाने में सहायता करती है । वर्ष 1993-94 के दौरान वस्त्र आधारित हस्तशिल्पों का जापान को दिए गए निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं है । तथापि, पिछले दो वर्षों अर्थात् 1991-92 और 1992-93 के दौरान उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वस्त्र आधारित हस्तशिल्प का जापान को किए गए निर्यात के मूल्य नीचे दिए गए हैं :–

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु० में)
1991-92	6.79
1992-93	9.41

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 1993-94 के दौरान जापान को वस्त्र आधारित हस्तशिल्प के हुए निर्यातों में मूल्य के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ग) चूंकि हस्तशिल्प के निर्यातों के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, इसलिए यह जानना संभव नहीं है कि मध्य प्रदेश राज्य से वस्त्र आधारित हस्तशिल्पों का निर्यात कितना हुआ है ।

(घ) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा जापान को निर्यात किए जाने वाले वस्त्र आधारित हस्तशिल्प के लिए 1994-95 के दौरान 19.2 करोड़ रु० का लक्ष्य रखा गया है ।

Modified Garment Export Policy

3848. SHRI SOM PAL : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) what objectives the modified policy of garment export is expected to serve;

(b) whether Government are aware of the reports of tax concessions to exporters being misused for money laundering;

(c) if so, what steps are being taken to check the malpractices; and

(d) if not, whether Government would try to find out such incidents and if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) The current Long Term Garment Export Entitlement Distribution Policy (1994-96) (Quota Policy) which is designed to be exporter friendly aims at encouraging increased unit value realisation for quota items simplification of procedures both relating to quota distribution as well as utilisation, greater transparency in the quota policy and effective measures for prevention of malpractices.

(b) to (d) The quota policy does not deal with tax concessions. Tax Concessions to exporters are mainly in the shape of deductions from income under Section 80 HHC of the Income Tax Act. 100% of export profits, as defined in the Income Tax Act, are exempt from tax. Such deductions are allowed on the basis of evidence produced by the exporters.

Golden hand-shake for workers of sick textile mills in Maharashtra

3849. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) whether the Maharashtra Government has proposed to offer a golden handshake to the workers of the sick textile mills in that State going on voluntary retirement at the rate fixed for workers of the NTC mills, to be paid out of the National Renewal Fund;

(b) if so, what is the precise proposal and the estimated amount involved in the scheme; and

(c) what is Government's derision thereon ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

हथकरघा विकास केन्द्र और रंगाई (डाइंग) एककों की स्थापना

3850. **श्री वीरेन जे० शाह** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग के विकास और विस्तार के लिए देशभर में

3,000 हथकरघा विकास केन्द्र तथा 500 क्वालिटी डाइंग एकक स्थापित करने का निर्णय लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और जनवरी, 1994 तक ऐसे कुल कितने केन्द्र देश भर में स्थापित किए गए हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सभी केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई अंतिम समय-सीमा निर्धारित की है ;

(घ) यदि हां, तो वह समय-सीमा क्या है और इस योजना के क्रियान्वयन पर कुल कितनी राशि का व्यय किए जाने की संभावना है : और

(ङ) जनवरी, 1994 तक इन हथकरघा विकास केन्द्रों पर उनके रख-रखाव और कार्यकरण के लिए औसतन कितनी राशि प्रति वर्ष व्यय की जा रही है और इन केन्द्रों द्वारा हथकरघा इकाइयों को कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाऐंगी ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) :(क) जी, हां ।

(ख) इस योजना की मार्गदर्शिका सितम्बर, 1993 में परिचालित की गई थी । मार्च 1994 के अंत तक 267 हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायता जारी की गई थी तथा 66 केन्द्रों में उत्कर्ष रंगाई केन्द्रों की स्थापना के लिए भी सहायता दी गई ।

(ग) और (घ) यह योजना वर्ष 1993-94 के आरंभ से आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित की गई। इस योजना का कुल परिव्यय 849 करोड़ रुपये है जिसमें से 321 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के अनुदान के रूप में और 528 करोड़ रुपये ऋण के रूप में दिए जाएंगे ।

(ङ) हथकरघा विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान 10 करोड़ रुपये की राशि प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई । यह सहायता एक समय के लिए है । ये केन्द्र प्राथमिक हथकरघा सहकारी समितियों के रूप में कार्य करेंगे जिससे अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे और इन प्राथमिक समितियों की सदस्यता में भी वृद्धि हो सकेगी ।

Sick textile units of NTC

3851. SHRI RAJNI RANJAN SAHU : Will the Minister of TEXTILES be pleased to state :

(a) the number of sick textile units under National Textile Corporation and the accumulated loss incurred by each so far and the estimated accumulated loss this year; and

(b) what steps have been taken or are being taken to restore them health and how many and which of them have already been restored to health by the NTC so far?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): (a) A statement indicating the details of accumulated loss/ profit of the mills of the subsidiary corporations of NTC that have been declared to be sick by the Board for Industrial and Financial Reconstruction under the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 is enclosed (*See* below).

(b) Government had approved a Turn Around Strategy for NTC involving selective modernisation, financial and managerial restructuring and rationalisation of surplus work force under the Voluntary Retirement Scheme. A Special Committee was constituted by Government to review this Turn Around Strategy in view of the reservations expressed against it by various quarters. The Special Committee has accepted the fresh modernisation plan for the revival of the NTC that has been prepared by the Textile Research Associations on the instructions of the Ministry of Textiles. It is expected that NTC would attain viability within two years of the implementation of this plan which would require prior approval of the Board for Industrial and Financial Reconstruction under the provisions of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985.